Terms of Trade and Credibility of Indian Exporters in Gulf Area

*190. SHRI R. P. YADAV: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the country's terms of trade have sharply deteriorated and the credibility of Indian exporters in the Gulf has been eroded following the failure of many prestigious firms to meet delivery schedules in the recent months; and

(b) if so, the details of steps being proposed to be taken by Government to improve the terms of trade and ragain confidence in the export markets in the coming months?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES (SHRI Z. R. ANSARI): (a) It is correct that India's balance of trade with the Gulf Countries has become unfavourable recently. The factor responsible for this is large increase in our import bill on account of higher prices of petroleum and petroleum products. No serious complaints against prestigeous Indian exporting firms have come to Government's notice recently; nor can this be considered a factor in our balance of trade with these countries.

(b) Government are taking various measures to step up exports to countries in Gulf Area. These include *inter-alia* exchange of high level delegations, encouraging exchange of non-official trade delegations, participation in international fairs held in this region and providing facilities for increased participation in project activities in this region. Whereas no serious complaints have been received from this region recently, any complaints received are attended to promptly and all possible steps taken to ensure that there is no loss of credibility of Indian exporters.

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, इधर गल्फ देशों के साथ हमारा व्यापार कम हुआ है और हमारे माल का निर्यात घटा है । बदकिस्मती से हमारी अच्छी से अच्छी फर्म्ज भी समय पर सामान नहीं दे पाती हैं। इससे विदेश-व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी वजह से हमारे देश को कितना घाटा हुआ है और क्या इसका कारण हमारी फर्मों की लापरवाही है, या बिजली की कटौती है या मजदूरों की हड़ताल है ।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पिछले दो, ढाई साल में . . . . . .

एक माननीय सदस्य: जनता पार्टी की वजह से ।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी: मैं वह बात नहीं कहूंगा । अगर माननीय सदस्य कहना चाहते हैं, तो कह लें ।

पिछले दो, ढाई साल में हमारा बैलेंस आफ ट्रेड कम हुआ है, नैगेटिव साइड में गया है । लेकिन उसके बहुत से रीजन्ज थे, जो एक्सपोर्टर्ज के कंट्रोल के बाहर थे । मसलन-मैं गल्फ कंट्रीज के सिलसिले में अर्ज कर रहा हूं-बहुत सी चीजों में हमारा प्राडक्शन घटा है और उसकी वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं कर सके । जो मेन कनस्ट्रेंट्स रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स में कमी आई है, खास तौर से इन कन्ट्रीज में, उनमें कुछ चीजों की डामेस्टिक स्कोर्सिटी भी है । या डामेस्टिक मार्केट को देखते हुए कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन्ज लगाने पड़े हैं, जैसे ओनियम और पोटैटो पर, और आयरन एण्ड स्टील प्राडक्ट्स पर, क्योंकि इनका प्राडक्शन दो ढाई साल में गिरा था और उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में कुछ कमी आई । एक और वजह यह भी रही है कि शिपिंग का बाटलनैक रहा है । हमारे जहाजों की कमी, पोर्ट्स में कनजेस्चन या पोर्ट्स में स्ट्राइक्स भी ऐसे सबब रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स की कमिटमेंट वक्त पर पूरी नहीं हो सकी और इस लिए हमारा एक्सपोर्ट घटा है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव: मंत्री महोदय ने बताया कि हमारा सामान बाहर भेजने में कमी का कारण प्रोडक्शन की कमी और पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अधिक कीमत रही है। उन्होंने यह भी बताया है कि वह इस बारे में स्टेप्स ले रहे हैं और कुछ डेलीगेशन्ज विदेशों में भेजना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन डेलीगेशन्ज के बाहर जाने से सामान का प्रोडक्शन बढ़ेगा, या इन की पैट्रोलियम की कमी दूर होगी? इसलिए मैं इस सन्दर्भ में मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि ये गल्फ-देश हमें समय पर सामान दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते और नहीं दे सकते तो उस से हमारी प्रतिष्ठा पर आंच आती है या नहीं? यदि प्रतिष्ठा पर आंच आती है तो उस दिशा में हम क्या कुछ करना चाहते हैं? जैसे आप ने कहा कि उस का कारण है प्रोडक्शन की कमी या पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कमी तो इस को आप डेलीगेशन से कैसे दूर करेंगे यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : जहां तक प्रोडक्ट्स की कमी और इंडिजिनस प्रोडक्शन की कमी का सवाल है और उस की वजह से कमी आई है उस को दूर कर के प्रोडक्शन बढ़ाया जाय, यही इस का एक रास्ता है, इस के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जहां तक और दूसरे रीजन्स का सवाल है शिपिंग बाटलनेक्स या और स्ट्राइक्स वगैरह का उस में भी एक ऐसी डिसिप्लिन कायम करनी चाहिए जिस से वह बाटलनेक्स दूर हों। और जो ऐसी मामूली चीजें हैं, मामूली जो कम्प्लेंट्स आती हैं, जैसे यादव जी ने कहा.....

AN HON. MEMBER: The Minister is not replying to the question..... about delegations.

SHRI Z. R. ANSARI: I am coming to the question of delegations.

जहां तक एक्पोर्ट और विदेशों से तिजारत का सवाल है उस में डेलीगेशंस का एक बहुत बड़ा महत्व है। उस से ऐसी एक फिजा पैदा होती है, मुख्तलिफ जो हमारे यहां की इण्डस्ट्रियलिस्ट्स और एक्सपोर्टर्स हैं उन के और दूसरे देशों के इम्पोर्टस के बीच में ताल्लुकात पैदा होते हैं, उन की रिक्वायरमेंट हम को मालूम होती है और हमारी रिक्वायरमेंट उन को मालूम होती है। जिस स्पेसिफिकेशन का सामान हम दे सकते हैं यह उन को मालूम होता है। तो इन डेलीगेशंस से एक फिजा पैदा होती है और एक अच्छा वातावरण पैदा होता है। यह एक नार्मल प्रैक्टिस है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव: हमारे सवाल का जवाब नहीं आया। मूल सवाल के जवाब में मंत्री जी ने बताया कि प्रोडक्शन की कमी के कारण इंडस्ट्री वाले नहीं भेज पाये हैं और इस के बाद इन्होंने कहा कि हम डेलीगेशन भेज रहे हैं तो हम यह जानना चाहते हैं कि डेलीगेशन से प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे? इस का जवाब तो इन्होंने दिया नहीं।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: The Member is well aware that delegations cannot improve production. A delegation is not definitely going to improve the production. In order to improve production, we have taken various steps. (*Interruptions*). The delegation is going out to identify the commodities. Every time, we have to send the delegations to identify the commodities and to determine the quantum. This is the normal trade practice. Let the hon. Member understand the general practice. It is nothing new; and every year we have to send delegations to identify the commodities, to determine the quantum and to determine the delivery schedule. All these formalities have to be complied with.

श्री हीरालाल आर. परमार: हमारे देश में हर साल 5 लाख टन का हड्डियों का उत्पादन है और उस के बाइ-प्रोडक्शन की 8 इण्डस्ट्रीज हमारे यहां हैं जिन के लिये 80 हजार टन हड्डियों की जरूरत है। 4 लाख 20 हजार टन हड्डी इस तरह बच जाती है। इस का एक्सपोर्ट दो तीन साल पहले सरकार ने बन्द किया हुआ है। इस की वजह से हमारे यहां की 130 इण्डस्ट्रीज बन्द पड़ी हैं। तो इस का एक्सपोर्ट क्यों नहीं चालू किया जाता है? इस के लिये सरकार ने क्या सोचा है?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: So far as this item is concerned, it is the administrative Ministry, *viz.* the Ministry of Agriculture which thought that we should not export it, as a result of which we have put a ban. But we are taking it up with them, i.e. to enquire whether they are in a position to supply them. Sometimes it happens that in order to meet the domestic demand, we put a ban on export.

Setting up of Integrated Port Based Steel Plant

*191. SHRI LAKSHMAN MALLICK: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to set up an integrated port-based steel plant in the country other than at Paradeep; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) and (b). With a view to augmenting the steel making capacity in the country, Government have been exploring the possibilities of setting up a new port-based steel plant with technical and financial assistance from some of the developed countries. As a result, concrete proposals have been received from certain parties in West Germany, U.K. etc. These proposals including the question of final location as well as other terms and conditions are presently in various stages of detailed technical and financial evaluation and will have to be negotiated further with the parties concerned before a final decision can be taken.

SHRI LAKSHMAN MALLICK: Is it a fact that West Germany and U.K. firms have offered to set up a steel plant at Paradeep on turn-key basis?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: It is more or less on the turn-key basis. but we are not using that term. But all the formalities are not to be complied with, but substantially it is on the turn-key basis.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: The people of Orissa were very glad when the hon. Minister had been recently on tour to Orissa and categorically assured that there would be a shore-bound Steel Plant at Paradeep. It had already come out in the papers that West Germany and other countries sent their team to India, they also visited Paradeep and almost selected the site and that land has already been allotted, so far as this is concerned. I would like to know by what time all the decisions are going to be taken, say, within two months or three months to set up the steel plant at Paradeep.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: We are trying to expedite the matter and it is known to the hon. member that it is a project of more than Rs. 1500 crores. I have already explained that it will be financed 100 per cent by the foreign parties including on-shore parties. In view of that, it is taking some time, but we are in the process of negotiations with both the parties. We are trying to evaluate which will be more favourable to us; and after arriving at a decision, we will take the final decision.

Foreign Exchange Reserves

×

193. SHRI P. J. KURIEN:
SHRI P. K. KODIYAN:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the foreign exchange reserves have been steadily declining for the last one year;

(b) if so, the facts and reasons therefor; and

(c) what measures have been taken by Government to boost exports, particularly to Gulf and African countries?